भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1634

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

काम के घंटों में बढ़ोतरी

1634. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कार्य के घंटे बढ़ाकर 70 या 90 घंटे करने के प्रस्ताव को बढ़ावा देने वाले बड़े व्यापारिक घरानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इसके खिलाफ नए विनियामक उपाय शुरू करने का इरादा रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के नियमों का कोई मूल्यांकन किया है, जिसके अनुसार प्रति सप्ताह 48 घंटे या प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे काम करना अनिवार्य है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनके सीईओ और मालिकों ने 70 घंटे या 90 पर काम करने की वकालत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले दस वर्षों के दौरान ओवरटाइम काम के कारण हुई मौतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ओवरटाइम काम के खिलाफ और अधिक सख्त नियम लागू करने का इरादा रखती है, क्योंकि हमारा देश ओवरटाइम काम के कारण होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष देशों में से एक है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): 'श्रम' के, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आने के कारण, श्रम कानूनों को राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में लागू किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में, इसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से लागू किया जाता है, जबकि राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन, राज्य के श्रम प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मौजूदा श्रम कानूनों के अनुसार, काम के घंटों और समयोपरि (ओवरटाईम) आदि सहित कार्य दशाओं को कारखाना अधिनियम, 1948 और संबंधित राज्य सरकारों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के उपबंधों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। अधिकांश प्रतिष्ठान दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा प्रशासित होते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है। समयोपरि काम करने के कारण हुई मौतों का आंकड़ा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*****